PRGI No. UPHIN/25/A1698

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 043
दि. 12.06.2026, शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता में योग करेंगे पीएम मोदी, 40000 लोग होंगे साथ, गिनीज रिकॉर्ड बनाने की तैयारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में योग करेंगे। इसके साथ ही कोलकाता पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है। इस कार्यक्रम की तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं। दौरान कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे।

(जीएनएस)।

कोलकाताः अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को कोलकाता में आयोजित होने वाले भव्य योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं और आयोजकों का दावा है कि इस आयोजन के दौरान कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे।

योग दिवस की कैसी हैं तैयारियां

योग प्रशिक्षक और वीवाईएएसए कोलकाता के निदेशक डॉ अभिजीत घोष ने गुरुवार को बताया कि इस बार योग दिवस का फोकस पूरी तरह कोलकाता पर रहेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि योग दिवस की थीम और उसका प्रस्तुतीकरण इतने बड़े स्तर पर इतने कम समय में किया जा सकता है। राज्य सरकार के विभिन्न विभाग इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटे हुए हैं।

बंगाल में पीएम मोदी के साथ कितने लोग करेंगे योग?

डॉ. घोष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को आयोजित मुख्य कार्यक्रम में लगभग 30 से 40 हजार लोग एक साथ योगाभ्यास करेंगे। कार्यक्रम के आयोजन स्थल को लेकर अभी रेड रोड और ब्रिगेड मैदान के बीच अंतिम निर्णय होना बाकी है। बारिश के कारण ब्रिगेड मैदान में कुछ तकनीकी दिक्कतें सामने आई हैं, इसलिए रेड रोड पर आयोजन होने की संभावना भी जताई जा रही है।

योग दिवस पर बंगाल में बनेगा रिकॉर्ड

उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल कोलकाता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे बंगाल में योग का वातावरण बनाया जाएगा। गंगा नदी पर नावों में योगाभ्यास का भी आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि अभी तक 450 नावों पर योग का गिनीज रिकॉर्ड है, जबकि बंगाल में 500 नावों को एक साथ जोड़कर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी चल रही है। गंगा तट, सुंदरबन, गांवों और शहर की गलियों तक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि

इसका संदेश समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

आम लोगों के साथ योग करना पसंद करते हैं पीएम मोदी

योग के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए डॉ अभिजीत घोष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बेहद व्यस्त दिनचर्या के बावजूद प्रतिदिन योग के लिए समय निकालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आम लोगों के साथ योग करना पसंद करते हैं। उनके लिए कोई विशेष मंच या अलग व्यवस्था नहीं होती। अभ्यास शुरू होने के बाद वे जमीन पर बैठकर अन्य प्रतिभागियों के साथ योग करते हैं। योग को वैश्विक पहचान दिलाने में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका ऐतिहासिक रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सहित कई नेताओं ने योग किया, लेकिन योग को विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए जिस नेतृत्व की आवश्यकता थी, वह मोदी ने प्रदान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं योग को अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं।

पीएम मोदी का योग से कैसा जुड़ाव?

उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का योग से जुड़ाव वर्ष 2002 के आसपास गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू हुआ था। उस दौरान वीवाईएएसए संस्था की ओर से गुजरात में नौकरशाहों और अधिकारियों के लिए योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते थे। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के योग गुरु डॉ एचएन नागेंद्र उनके भी गुरु हैं और आज भी संस्था के प्रशिक्षक समय-समय पर दिल्ली जाकर योग प्रशिक्षण से जुड़े कार्यक्रमों में सहयोग करते हैं।

कोलकाता में कैसी तैयारियां?

आयोजन की तैयारियों पर डॉ. अभिजीत घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल का स्वास्थ्य विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय, पुलिस प्रशासन, कोलकाता नगर निगम और लोक निर्माण विभाग सहित विभिन्न एजेंसियां मिलकर कार्यक्रम स्थल को अंतिम रूप देने में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी जिस तरह से जुटी हुई है, वह अभूतपूर्व है। योग को धर्म से जोड़ने की बहस पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि योग किसी एक धर्म विशेष की परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक अभ्यास है। उन्होंने कहा कि यदि योग का प्रचार-प्रसार गांव-गांव तक पहुंचाना है, तो इसके सार्वजनिक प्रदर्शन और बड़े आयोजनों की आवश्यकता है। योग हर व्यक्ति के लिए है और इसका उद्देश्य शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है।

600 योग शिक्षकों और डेमोंस्ट्रेटरों का चयन

उन्होंने आगे बताया कि कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए लगभग 600 योग शिक्षकों और डेमोंस्ट्रेटरों का चयन किया गया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के परिसर में हाल ही में इनके चयन की प्रक्रिया पूरी हुई। अब इन प्रशिक्षकों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन अभ्यास सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि 21 जून को सभी प्रतिभागी एक समान योग प्रोटोकॉल का पालन कर सकें।

योगी से विजय तक, प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम की मुलाकातों ने बटोरी सुर्खियां

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक के दौरान और उसके बाद दिल्ली में कई ऐसी तस्वीरें सामने आईं, जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने मुलाकात की।

यह मुलाकातें ऐसे समय में हुई हैं जब प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में 'विकसित भारत 2047' के विजन, रोजगार, कौशल विकास, मानव संसाधन और राज्यों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्यमंत्री एक मंच पर नजर आए और केंद्र-राज्य सहयोग को लेकर अपने सुझाव भी रखे।

बैठक के बाद सामने आई तस्वीरों और वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते दिखाई दिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को 12वीं सदी के महान समाज सुधारक, दार्शनिक और लिंगायत संत जगद्गुरु बसवेश्वर (भगवान बसवन्ना) की चंदन की लकड़ी से निर्मित एक आकर्षक प्रतिमा भेंट की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये तस्वीरें सहकारी संघवाद और संवाद की राजनीति का संदेश देती हैं।

दिलचस्प बात यह है कि मुलाकात करने वाले मुख्यमंत्रियों में भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ-साथ कांग्रेस शासित तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार भी शामिल रहे। इससे यह संदेश गया कि विकास और नीति से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर संवाद जारी है।

नीति आयोग की बैठक को केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। इस बीच,

मुख्यमंत्री योगी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, सबसे लंबे कार्यकाल को लेकर दी बधाई

नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएमओ एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए पोस्ट किया, " सीएम योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात की।" सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, "145 करोड़ भारतीयों की सेवा, सुरक्षा और समृद्धि के लिए पूर्ण समर्पित तथा 'अमृतकाल' के सारथी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई।"

उन्होंने कहा, "भारतीय लोकतंत्र का यह अभूतपूर्व पड़ाव पूरे राष्ट्र के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है।

पीएम मोदी किस बात के लिए ट्रंप को थैंक्यू कह रहे हैं?' अमेरिकी हमले में भारतीयों की मौत पर भड़के केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद कहने पर सवाल उठाया है। केजरीवाल ने मोदी के ट्रंप को धन्यवाद कहने पर सवाल उठाया भारतीय नागरिकों की जान जाने के बाद धन्यवाद पर आपत्ति केजरीवाल बोले, भारत को मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद कहने पर ह्लआपह्व के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया है।

उनका कहना है कि जब भारतीय नागरिकों ने अपनी जान गंवा दी है, तो प्रधानमंत्री आखिर डोनाल्ड ट्रंप को किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं?

केजरीवाल ने एक्स पर साधा पीएम पर निशाना

केजरीवाल ने एक्स पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को धन्यवाद कह रहे हैं। आखिर किस बात के लिए धन्यवाद? उन जहाजों पर हमला करने के लिए जिन पर भारतीय सवार थे और भारतीय नागरिकों की जान लेने के लिए? अब यह स्थिति हमारे देश के लिए बेहद शर्मनाक हो चुकी है।

केजरीवाल ने आगे कहा, मोदी जी ने भारत की संप्रभुता, गौरव और अपने नागरिकों की जान पूरी तरह से ट्रंप के हवाले कर दी है। भारत को एक मजबूत प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। ट्रंप को हमारे देश और हमारे लोगों के साथ अपनी मनमानी करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती।

लंबित तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों के दोहन से जुड़ा सालों पुराना विवाद सुलझा! 50-50 पर बनी सहमति, अमित शाह बोले-बदलेगा पूर्वोत्तर

(जीएनएस)।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार, 11 जून को भारत सरकार, असम सरकार और नागालैंड सरकार के बीच हुए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) को पूर्वोत्तर भारत के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।

इस समझौते के जरिए दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों के दोहन से जुड़े मुद्दों का समाधान निकालने की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है।

दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह केवल एक प्रशासनिक या आर्थिक समझौता नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समृद्ध और विकसित पूर्वोत्तर के विजन को साकार करने की दिशा में एक अहम उपलब्धि है।

समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान अमित शाह ने कहा कि आज का दिन पूर्वोत्तर भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित कई जटिल मुद्दों को बातचीत और सहयोग के माध्यम से हल करने का प्रयास किया गया है और यह समझौता उसी का परिणाम है। गृह मंत्री ने कहा कि इस पहल से तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं उत्पादन की संभावनाओं को नई गति मिलेगी। साथ ही, इससे भविष्य में खनिज संसाधनों के दोहन और खनन गतिविधियों के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे।'

अमित शाह ने बताया कि दोनों राज्यों ने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए तेल और गैस संसाधनों के उपयोग को लेकर 50-50 हिस्सेदारी के मॉडल पर सहमति बनाई है। उन्होंने कहा कि असम और नागालैंड दोनों ने यह समझा कि सीमावर्ती विवादों या अन्य प्रशासनिक चुनौतियों को देश की प्राकृतिक संपदा के उपयोग में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। इसी सोच के तहत दोनों राज्यों ने साझा लाभ के सिद्धांत को अपनाया। गृह मंत्री के अनुसार, यह केवल आर्थिक समझौता नहीं बल्कि राष्ट्र प्रथम की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है।

कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने नागालैंड के मुख्यमंत्री का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने केवल छह तेल क्षेत्रों तक सीमित रहने के बजाय पूरे नागालैंड में तेल और गैस अन्वेषण के लिए सकारात्मक रुख दिखाया है। उन्होंने कहा कि नागालैंड सरकार की यह पहल राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती है और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित कर सकती है। गृह मंत्री ने इसके लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका सहयोग और दूरदर्शिता इस समझौते को सफल बनाने में महत्वपूर्ण रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते से पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऊर्जा क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन बढ़ने से न केवल राज्यों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके अलावा, तेल एवं गैस क्षेत्र से जुड़ी आधारभूत संरचना, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और सेवा क्षेत्र में भी निवेश बढ़ने की संभावना है।

ऐतिहासिक समझौते से बढ़ी उम्मीदें

भारत सरकार, असम और नागालैंड के बीच हुए इस त्रिपक्षीय समझौते को पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। केंद्र सरकार का मानना है कि इससे क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और विकास की नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास जताया कि यह समझौता आने वाले वर्षों में पूर्वोत्तर भारत को आर्थिक प्रगति और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

जिन क्षेत्रों में भूमि के मालिकाना हक को लेकर अभी भी पूरी तरह अस्पष्टता है, वहां से होने वाली कमाई को एक 'एस्क्रो अकाउंट' में सुरक्षित रखा जाएगा, जब तक कि उसका अंतिम कानूनी समाधान नहीं हो जाता। असम और नागालैंड के बीच लगभग 434 किलोमीटर लंबी सीमा साझा होती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों से ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया

प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों से ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत तेजी से खेलों का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है।

उन्होंने ओलंपिक की तैयारियों को विकसित भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया। साथ ही, विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में खेल जगत में भारत की पहचान और मजबूत होगी।

जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात, राज्य का दर्जा बहाल करने की फिर उठाई मांग

(जीएनएस)।

श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ भेंट कर, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ जम्मू कश्मीर के विकासात्मक और प्रशासनिक मुद्दों पर भी चर्चा की और प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार, विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने तथा पर्यटन को प्रोत्साहित करने में विशेष सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया।

यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा ,जम्मू कश्मीर में एक बड़ा राजनीतिकि मुद्दा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य के दर्जे की बहाली के लिए मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली में धरना भी देने का एलान किया है। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मुलाकात में राज्य के दर्जे की बहाली पर हुई चर्चा को बहुत अहम माना जा

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ अपनी मुलाकात की जानकारी अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी से जम्मू-कश्मीर से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

बातचीत में राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति बढ़ाने और पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने जैसे विषय शामिल रहे। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को लगातार 12 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने की उपलब्धि पर बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि यह भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।

वहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर जम्मू-कश्मीर से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

हमले से ठीक पहले युद्ध से पीछे हटे ट्रंप! ईरान पर बमबारी रोकी, कहा-डील पर बनी सहमति

(जीएनएस)।

मिडिल ईस्ट में पिछले 100 से अधिक दिनों से जारी भीषण युद्ध और परमाणु महाविनाश के खतरे के बीच एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर गुरुवार, 12 जून को देर रात होने वाले अमेरिकी सेना के बड़े हवाई हमलों और बमबारी को ऐन वक्त पर रोक दिया है।

ट्रंप ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक बेहद चौंकाने वाला और ऐतिहासिक पोस्ट साझा करते हुए एलान किया है कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व के साथ सीधी बातचीत बेहद ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है और दोनों देश एक बड़े शांति समझौते के अंतिम पड़ाव पर हैं।

इस समझौते को इजरायल, सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित दुनिया के कई प्रमुख देशों ने अपनी मंजूरी दे दी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने

वाशिंगटन के समय के अनुसार गुरुवार दोपहर (11 जून 2026) को किए अपने पोस्ट में लिखा-इस तथ्य के आधार पर कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बातचीत को ईरानी नेतृत्व के सर्वोच्च स्तर तक ले जाया गया है और वहां से इसे मंजूरी मिल गई है, मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में आज शाम ईरान के खिलाफ होने वाले निर्धारित हमलों और बमबारी को रद्द कर दिया है।

ट्रंप ने आगे बताया कि इस समझौते के मसौदे पर केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि क्षेत्र के तमाम बड़े देश एकमत हैं-बातचीत और इसके अंतिम बिंदुओं को, वैचारिक रूप से और पूरी बारीकी के साथ, इसमें शामिल सभी पक्षों द्वारा अप्रुव कर दिया गया है।

इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, मिस्र और अन्य देश शामिल हैं।

बंगाल सीआईडी ने हस्ताक्षर जालसाजी मामले की जांच में अभिषेक बनर्जी से छह घंटे तक पूछताछ की।

गुरुवार रात पश्चिम बंगाल सीआईडी मुख्यालय में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से एक हस्ताक्षर जालसाजी मामले के संबंध में लगभग छह घंटे तक पूछताछ की गई। यह

पूछताछ राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में पार्टी की पसंद से संबंधित है। बनर्जी सीआईडी कार्यालय लगभग 5.50 बजे पहुंचे और रात लगभग 11.30 बजे वहां से निकले, उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। बनर्जी ने पहले स्वास्थ्य समस्याओं और कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक लंबित याचिका का हवाला देते हुए जांच एजेंसी द्वारा जारी की गई तीन समन को छोड़ दिया था।

लखनऊ : युवक को बंधक बनाकर लोहे की रॉड से पीटा, हालत गंभीर; आरोपितों की तलाश में जुटी पुलिस

(जीएनएस)।

लखनऊ। बीबीडी इलाका स्थित बीसीसी शक्ति अपार्टमेंट में युवक को वहीं रहने वाले युवकों ने बंधक बनाकर पीटा। पीड़ित के पिता ने अपार्टमेंट में रहने वाले एक युवक और उसके साथियों पर बंधक बनाकर पीटने, मोबाइल तोड़ने और जान से मारने की धमकी देने की तहरीर स्थानीय थाने में दी। इंस्पेक्टर बीबीडी राम सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

तिवारीगंज स्थित बीसीसी शक्ति अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर-814 निवासी पंकज यादव के मुताबिक,

सात जून की रात उनका बेटा मयंक दैनिक उपयोग का सामान लेकर लिफ्ट से ऊपर जा रहा था। इसी दौरान फ्लैट नंबर-401 में रहने वाले विपिन कुमार सिंह अपने साथियों अनुराग मिश्रा, अभि ठाकुर और राज मिश्रा के साथ वहां पहुंचे और उनके बेटे को धक्का दे दिया।

बेटे को लिफ्ट से बाहर खींचा

आरोपितों ने उनके बेटे को लिफ्ट से बाहर खींच लिया। गालियां दी, करीब 20 मिनट तक बंधक बनाकर पीटा। लोहे के पाइप से हमला किया गया। सिर व शरीर के कई हिस्सों में चोट आईं हैं। मोबाइल भी तोड़ दिया।

बेहोश होने पर उस पर पत्थर से वार किया गया। पिता ने बताया कि आरोपित अपराधी हैं। पूरा परिवार दहशत में है। इंस्पेक्टर राम सिंह के मुताबिक सीसी फुटेज की मदद से मामले में साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं।

लखनऊ का कायाकल्प: एलडीए तोड़ेगा कैलाशकुंज और विकासदीप कॉम्प्लेक्स, 110 करोड़ से बनेंगे 13 मंजिला मॉल और प्रीमियम फ्लैट्स

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुसैनगंज का विकासदीप, इंदिरा नगर का कैलाशकुंज, अलीगंज और कपूरथला के पुराने व्यावसायिक परिसरों को तोड़कर उनकी री-स्ट्रक्चरिंग और री-मॉडलिंग की जाएगी. इस महायोजना की शुरूआत सबसे पहले इंदिरा नगर के कैलाश कुंज कॉम्प्लेक्स से होगी और धीरे-धीरे यह सिलसिला आगे बढ़ेगा.

लखनऊ विकास प्राधिकरण अब शहर के इन सभी बेहद पुराने और जर्जर हो चुके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नए सिरे से बहुमंजिला बनाने जा रहा है. इसकी शुरूआत अयोध्या रोड पर स्थित करीब 40 साल पुराने प्रसिद्ध कैलाशकुंज कॉम्प्लेक्स को ढहाने के साथ की जाएगी.

कैलाशकुंज की जगह बनेगी 13 मंजिला आधुनिक इमारतः यहां की वर्तमान जर्जर हो चुकी 13 मंजिला पुरानी बिल्डिंग को पूरी तरह से तोड़कर उसकी जगह एक नई और बेहद आधुनिक गगनचुंबी बिल्डिंग बनाई जाएगी. एलडीए की नई योजना के मुताबिक इसमें नीचे के फ्लोर पर दुकानें और कॉर्पोरेट ऑफिस रहेंगे, जबकि ऊपर की मंजिलों पर प्रीमियम आवासीय फ्लैट्स बनाए जाएंगे. एलडीए का दृढ़ मानना है कि यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आगे चलकर लखनऊ में शहरी री-डेवलपमेंट (पुनर्विकास) का पहला बेहतरीन उदाहरण बनेगा. वर्तमान में कैलाशकुंज कॉम्प्लेक्स प्राइम लोकेशन पर कुल 6046 वर्गमीटर की विशाल सरकारी जमीन पर बना हुआ है.

जर्जर दुकानों और अवैध कब्जों पर LDA का एक्शनः इस पुराने परिसर में करीब 280 दुकानें मौजूद हैं, लेकिन 40 साल पुरानी होने के कारण इसकी मुख्य बिल्डिंग कई जगहों से तकनीकी रूप से बेहद कमजोर हो चुकी है. हाल ही में जब एलडीए की टीम ने इसका विस्तृत सर्वे कराया, तो पता चला कि बहुत सी दुकानें यहाँ सालों से बंद पड़ी हैं. इसके साथ ही परिसर के कॉमन एरिया और पार्किंग स्पेस में भी स्थानीय

लोगों ने अवैध रूप से पक्का कब्जा कर रखा है. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि यह जगह अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग के पास बेहद शानदार और महंगी लोकेशन पर स्थित है.

PPP मॉडल रद्द, अब छज्झ खुद खर्च करेगा 110 करोड़ः परंतु समय पर रखरखाव न होने और बिल्डिंग के अत्यधिक पुरानी पड़ जाने से इस बेशकीमती जमीन का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है. इसलिए जनसुरक्षा और सुंदरीकरण के मद्देनजर इसे पूरी तरह तोड़कर नई बहुमंजिला बिल्डिंग बनाने का कड़ा फैसला लिया गया है. एलडीए अब खुद अपने स्तर पर इस बड़े प्रोजेक्ट का निर्माण कराएगा और इसके लिए बजट जारी कर दिया गया है. पहले इसे PPP मोड यानी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर बनाने का प्लान था, लेकिन अब प्राधिकरण अपने स्वयं के खर्चे पर काम करेगा.

पुराने दुकानदारों को मिलेगा सवा गुना बड़ा स्पेसः प्रस्ताव के अनुसार, नई बनने वाली आधुनिक बिल्डिंग करीब 45 मीटर ऊंची होगी और इसमें कुल 13 मंजिलें तैयार की जाएंगी. इस पूरे प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने में एलडीए द्वारा करीब 110 करोड़ रुपये की भारी रकम खर्च की जाएगी. इसके नीचे की तीन मंजिलों यानी भूतल (ग्राउंड फ्लोर), पहले और दूसरे तल पर व्यावसायिक दुकानें और ऑफिस स्पेस दिया जाएगा. इसके ऊपर की बची हुई सभी मंजिलों पर आधुनिक सुविधाओं से लैस 3 BHK वाले प्रीमियम फ्लैट बनाए जाएंगे.

कैलाशकुंज के बाद अलीगंज और गोमती नगर की बारीः इस री-डेवलपमेंट योजना से कैलाशकुंज के पुराने और पंजीकृत दुकानदारों को सीधा और बड़ा आर्थिक फायदा मिलने वाला है. एलडीए के अधिकारी वर्तमान में उन सभी दुकानदारों से सीधे बात करके इस संबंध में विधिक सहमति ले रहे हैं. आपसी बातचीत में तय हुआ है कि पुरानी बिल्डिंग में जिनकी जितनी बड़ी दुकान है, उन्हें नई बिल्डिंग में उससे सवा गुना बड़ा एरिया दिया जाएगा. उदाहरण के लिए, अगर किसी आवंटी की पुरानी दुकान 100 वर्गफुट की है, तो नई आलीशान बिल्डिंग में उसे 125 वर्गफुट की बड़ी दुकान मिलेगी.

उजाला कॉम्प्लेक्स का भी बदलेगा नक्शा, तैयारी तेजः इससे पुराने वैध आवंटियों को भी पहले से बड़ा और बेहतर माहौल में अपना कारोबार करने का एक सुनहरा मौका मिलेगा. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके इस प्रस्ताव को जल्द अंतिम रूप देने के कड़े निर्देश दिए हैं. उनका स्पष्ट कहना है कि कैलाशकुंज को पूरे लखनऊ के लिए री-डेवलपमेंट का एक रोल मॉडल बनाया जाएगा. उन्होंने आगामी योजनाओं का खुलासा करते हुए बताया कि इसके तुरंत बाद अलीगंज और गोमती नगर की व्यावसायिक संपत्तियों की बारी है.

अलीगंज में बनेगी 14 मंजिला भव्य विंगः एलडीए अपनी इस महत्वाकांक्षी पुनर्विकास योजना के तहत सिर्फ कैलाशकुंज कॉम्प्लेक्स तक ही सीमित नहीं रहने वाला है. अलीगंज के सेक्टर-जी में स्थित पुराने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के लिए भी इसी तर्ज पर री-डेवलपमेंट का नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. अलीगंज का यह पुराना कमर्शियल कॉम्प्लेक्स करीब 11,000 वर्गमीटर में फैला है और इसमें वर्तमान में करीब 100 दुकानें संचालित हैं. यहाँ पर एलडीए द्वारा 14 मंजिला नई और भव्य कमर्शियल-कम-रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाने का मास्टर प्लान तैयार किया गया है.

250 नई दुकानें और 72 प्रीमियम फ्लैट्स का तोहफाः इस प्रस्तावित अलीगंज प्रोजेक्ट के तहत नई बिल्डिंग में 250 आधुनिक दुकानें और 72 आलीशान आवासीय फ्लैट बनाए जाएंगे. यहाँ बनने वाले सभी फ्लैट भी उच्च आय वर्ग के लिए 3 BHK कैटेगरी के ही निर्धारित किए गए हैं. इसके अलावा, पॉश इलाके गोमती नगर में स्थित पुराने 'उजाला कॉम्प्लेक्स' को भी दोबारा से आधुनिक स्वरूप में बनाने की योजना पर काम चल रहा है. इस व्यापक कदम से लखनऊ के पुराने बाजारों का कायाकल्प होगा और शहर को जाम व जर्जर भवनों से मुक्ति मिलेगी.

अर्पण केंद्र क्या है? दिल्ली के 10 मेट्रो स्टेशन पर हो रही शुरू ये सुविधा, इस नयाब पहल के बारे में

(जीएनएस)।

अक्सर में बगैर इस्तेमाल के कपड़े अलमारी में जगह घेरते हैं। अगर आप भी ऐसे कपड़ों को फेंकने के बजाय उनका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दिल्ली में बढ़ते टेक्सटाइल कचरे को कम करने और जरूरतमंदों तक उपयोगी संसाधन पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार और DMRC ने एक नई पहल शुरू करने का फैसला किया है।

'

अर्पण केंद्र' नाम की इस योजना के तहत मेट्रो यात्रियों को पुराने और उपयोग योग्य कपड़े दान करने की सुविधा मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य कपड़ों की बबार्दी रोकना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और पुनर्चक्रण के जरिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।

क्या है 'अर्पण केंद्र'?

'अर्पण केंद्र' एक विशेष कपड़ा दान अभियान है, जिसके तहत दिल्ली के प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर कलेक्शन बॉक्स लगाए जाएंगे। यात्री अपने घरों में पड़े पुराने लेकिन उपयोग योग्य कपड़ों को इन बॉक्स में जमा कर सकेंगे। इससे लोगों को कपड़े दान करने के लिए अलग से किसी संस्था या केंद्र तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कपड़ों को मिलेगा नया जीवन

कलेक्शन बॉक्स में जमा किए गए कपड़ों को उनकी स्थिति और उपयोगिता के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की मदद से इन कपड़ों को रिसाइकिल कर नए और उपयोगी उत्पादों में बदला जाएगा। इस प्रक्रिया से संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

टेक्सटाइल कचरे की समस्या से निपटने की कोशिश

विशेषज्ञों के अनुसार, टेक्सटाइल वेस्ट आज पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। हर साल बड़ी मात्रा में फेंके जाने वाले कपड़े लैंडफिल साइट्स पर दब जाते हैं, जिससे प्रदूषण और कचरे की समस्या बढ़ती है। 'अर्पण केंद्र' पहल इस चुनौती से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यह अभियान स्वच्छ, हरित और टिकाऊ दिल्ली के लक्ष्य को भी मजबूती देगा।

इन 10 मेट्रो स्टेशनों पर लगाए जाएंगे कलेक्शन बॉक्स

योजना के पहले चरण में दिल्ली के 10 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर कपड़ा संग्रह केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें शाहदरा (रेड लाइन), मोहन एस्टेट (वायलेट लाइन), रोहिणी वेस्ट (रेड लाइन), लाजपत नगर (वायलेट और पिंक लाइन), मालवीय नगर (येलो लाइन), मयूर विहार फेज-क (ब्लू और पिंक लाइन), हौज खास (येलो और मैजेंटा लाइन), पंजाबी बाग वेस्ट (पिंक और ग्रीन लाइन), द्वारका (ब्लू लाइन) और शालीमार बाग (पिंक लाइन) मेट्रो स्टेशन शामिल हैं।

सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ

इस पहल से न केवल कपड़ों की बबार्दी कम होगी, बल्कि जरूरतमंद समुदायों तक संसाधन पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। साथ ही, रिसाइक्लिंग और अपसाइक्लिंग गतिविधियों को बढ़ावा मिलने से स्थानीय स्तर पर आजीविका के नए अवसर भी विकसित हो सकेंगे। 'अर्पण केंद्र' को दिल्ली में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

समाज और संस्कृति को सही दिशा देता है अच्छा साहित्य

मुंबई, 11 जून। प्रतीक्षा मेमोरियल एज्युकेशनल ट्रस्ट, मुंबई के 20 वें वार्षिक सम्मेलन का गरिमापूर्ण समारोह बुधवार, 10 जून, 2026 को

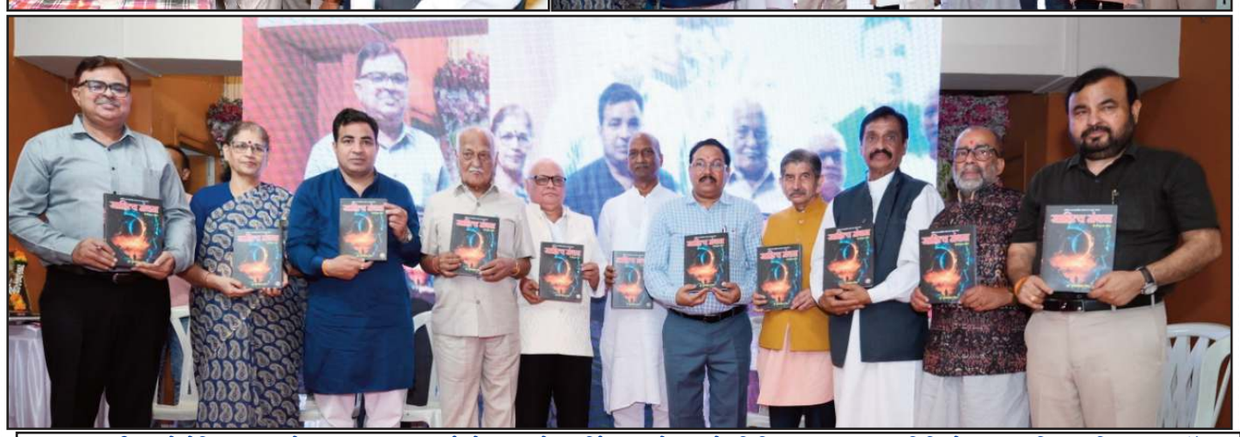

प्रतीक्षा मेमोरियल एज्युकेशनल ट्रस्ट, मुंबई के 20 वें वार्षिक सम्मेलन में विभिन्न गणमान्य अतिथियों द्वारा वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. कृपाशंकर मिश्र द्वारा नवसृजित हिन्दी काव्य-संग्रह "साहित्य मंथन" के लोकार्पण तथा सबके द्वारा डॉ. मिश्र के सामूहिक अभिनंदन का दृश्य। तीसरे चित्र में लोकार्पण समारोह की शुरूआत में दीप प्रज्ज्वलन करते हुए समारोह के अध्यक्ष डॉ. सुधाकर मिश्र।

मुंबई के प्रमुख उपनगर गोरेगाँव के केशव गोरे सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें मंच पर उपस्थित विभिन्न प्रबुद्ध और गणमान्य अतिथियों ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. कृपाशंकर मिश्र द्वारा नवसृजित हिन्दी काव्य-संग्रह "साहित्य मंथन" का लोकार्पण किया। डॉ. मिश्र की नवीनतम पुस्तक पर परिचर्चा के दौरान विभिन्न अतिथि वक्ताओं ने कहा कि अच्छा साहित्य हमेशा समाज एवं संस्कृति को सही दिशा देता है और इस कसौटी पर डॉ. मिश्र की सभी पुस्तकें पूरी तरह खरी उतरती हैं।

इस सुरुचिपूर्ण समारोह की अध्यक्षता हिन्दी साहित्य के वरिष्ठतम हस्ताक्षर डॉ. सुधाकर मिश्र ने की। उन्होंने अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में डॉ. कृपाशंकर मिश्र की सृजनधर्मिता एवं लेखकीय गुणवत्ता की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए उनका हार्दिक अभिनंदन किया और उनकी भावी सृजन यात्रा के लिए अनंत शुभकामनाएँ दीं। परिचर्चा में भाग लेने वाले मनीषियों में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के निवर्तमान कार्याध्यक्ष डॉ. शीतला प्रसाद दुबे, मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. करुणा शंकर उपाध्याय, वरिष्ठ साहित्यकार एवं प्रमुख राजनेता प्रो. डॉ. दयानंद तिवारी, वरिष्ठ विदुषी डॉ. उषा मिश्रा, वरिष्ठ शायर डॉ. सागर त्रिपाठी, वाराणसी से आये विद्वान डॉ. कपिलदेव प्रसाद मिश्र, नागपुर से पधारे वरिष्ठ साहित्यकार श्रीराम कृष्ण सहस्रबुद्धे, राजकुमार मिश्र और समारोह का कुशल संचालन कर रहे डॉ. उमेशचंद्र शुक्ल ने "साहित्य मंथन" पुस्तक और डॉ. कृपाशंकर मिश्र की सृजन यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर अपने विस्तृत एवं समीक्षात्मक विचार प्रकट किये। समारोह का शुभारम्भ जाने-माने संस्कृत विद्वान श्रीराम व्यास उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना, डॉ. सुधाकर मिश्र एवं अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन तथा सुश्री कनिष्का अंकित मिश्रा द्वारा गणेश स्तुति पर प्रस्तुत आकर्षक कत्थक नृत्य के साथ हुआ। सभी का स्वागत करते हुए संस्था के अध्यक्ष डॉ. कृपाशंकर मिश्र ने अपनी प्रस्तावना में समारोह के सम्पूर्ण नियोजन एवं संस्था की प्रमुख गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर वरिष्ठ गीतकार एवं मीडिया सलाहकार गजानन महतपुरकर, मशहूर फिल्मी गीतकार डॉ. देवमणि पांडेय, वरिष्ठ साहित्यकार बोधिसत्व, डॉ. नीलिमा पाण्डेय, श्रीमती आभा बोधिसत्व, श्रीमती सत्यभामा सिंह, राजकुमार मिश्र, डॉ. दिनेश वर्मा, डॉ. रोशनी किरण, डॉ. किरण मिश्रा, श्रीमती पल्लवी रानी, श्रीमती किरण तिवारी और ओमप्रकाश तिवारी सहित विभिन्न वरिष्ठ कलमकारों को संस्था की ओर से प्रशस्ति-पत्र, पुष्प गुच्छ तथा नवलोकार्पित पुस्तक की प्रति देकर एवं शॉल ओढ़ाकर "साहित्य गौरव सम्मान" से सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले अन्य कलमकारों में शिवप्रकाश जौनपुरी, मनोज नायक, लाल बहादुर कमल, नन्दन मिश्र त्यागी, सुरेश मिश्र, मिथिलेश मिश्र, प्रमोद उपाध्याय, नीतू पाण्डेय क्रान्ति, राजेन्द्र मिश्र, डॉ. मृदुल तिवारी महक, वाचस्पति तिवारी, श्रीधर आत्मिक मिश्र, प्रमोद पाण्डेय, विनोद पाण्डेय, रामजीत गुप्त, नन्दलाल क्षितिज, ए. पी. द्विवेदी, श्रीमती रोमा झा, श्रीमती कुसुम तिवारी, इन्दिरा तिवारी, श्रीमती अमिता गुजराल, श्रीमती जागृति सिन्हा, राजनाथ शर्मा, हरिशंकर मिश्र, संतोष मिश्र, सुरेश दुबे, कृष्ण कान्त मिश्र, राम सिंह, अमरनाथ तिवारी, गौरी शंकर तिवारी, हरिश्चंद्र पाण्डेय, आनन्द पाण्डेय केवल, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, विनय शर्मा दीप, अरुण दुबे, डॉ. प्रमोद पाण्डेय, सूर्यकुमार तिवारी एवं समस्त मानस ट्रस्ट परिवार, संजय द्विवेदी, अनिल कुमार राही, राकेशमणि तिवारी, आर के सर चुलबुल, अवधेश विश्वकर्मा और एस वी राघवन शामिल हैं। समारोह के संयोजन में वसीम और उनके सक्रिय सहयोगियों ने समर्पित भाव से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में संस्था के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. कृपाशंकर मिश्र ने सभी के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त किया।

ग्लोबल अय्यप्पा सम्मेलन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लेफ्ट... एक संगम जिसने केरल चुनाव के नतीजे बदल दिए

(जीएनएस)।

क्या केरल में सत्ता परिवर्तन में धर्म की राजनीति की भी बड़ी भूमिका थी? विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के बाद लेफ्ट फ्रंट एलडीएफ का नेतृत्व करने वाली सीपीएम ने ही यह बात स्वीकार की है. सीपीएम का यह भी मानना है कि ग्लोबल अय्यप्पा सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ का संदेश पढ़ा जाना भी नुकसानदेह साबित हुआ.

केरलम में विधानसभा चुनाव से पहले एक सम्मेलन हुआ था. ग्लोबल अय्यप्पा सम्मेलन. 20 सितंबर को सम्मेलन का आयोजन सबरीमाला अय्यप्पा मंदिर के पास पंपा में हुआ था. केरलम में सत्ता परिवर्तन के करीब महीना भर बाद ग्लोबल अय्यप्पा सम्मेलन का खास तौर पर जिक्र हो रहा है, और केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पी. विजयन की हार की एक बड़ी वजह माना जा रहा है.

खास बात यह है कि सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक संदेश भी पढ़ा गया था. ऐसा तब हुआ जब केरलम बीजेपी के नेता भी सरकारी आयोजन का विरोध कर रहे थे. बिल्कुल वैसे ही जैसे कांग्रेस और बाकी यूडीएफ नेताओं की तरफ से

तत्कालीन मुख्यमंत्री पी. विजयन की आलोचना हो रही थी. नेताओं का आरोप था कि सीपीएम धर्म और राजनीति को मिलाकर चुनाव जीतने के लिए हिंदू कार्ड का इस्तेमाल कर रही है.

केरलम विधानसभा चुनावों में एलडीएफ की हार की विस्तृत समीक्षा के बाद CPI(M) के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने माना है कि ऐसी चीजों से गलत संदेश गया, जो एलडीएफ की हार की वजह बना. प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमवी गोविंदन ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का संदेश पढ़ा जाना भी सही नहीं था.

ग्लोबल अय्यप्पा सम्मेलन त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के 75 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किया गया था. आयोजन के पीछे तत्कालीन मुख्यमंत्री और एलडीएफ नेता का मकसद था, सबरीमाला को वैश्विक तीर्थस्थल बनाना, अय्यप्पा में आस्था रखने वाले हिंदू श्रद्धालुओं को बुलाना - और 2018-19 के सबरीमाला विवाद के बाद खराब हुई छवि को सुधारने का प्रयास करना. असल में, सबरीमाला विवाद के दौरान मंदिर में महिलाओं के प्रवेश मुद्दे पर पी. विजयन सरकार के स्टैंड से लोगों में भारी नाराजगी देखी गई थी.

और अब CPI(M) स्वीकार कर रही है कि 2025 में हुए ग्लोबल अय्यप्पा डिवोटीज कॉन्फ्रेंस, जिसे हिंदू वोटर को साधने की एक और कोशिश के रूप में देखा गया, पूरी तरह उल्टा पड़ गया. उढक्(ट) के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने मीडिया से कहा, अय्यप्पा सम्मेलन का आयोजन देवस्वम बोर्ड ने किया था... लेकिन, इसे सरकारी आयोजन के रूप में प्रचारित किए जाने के कारण लोगों में भ्रम पैदा हुआ... आरएसएस के प्रमुख नेताओं में से एक, योगी आदित्यनाथ का संदेश पढ़ना सही नहीं था.

केंद्र सरकार के ऐतिहासिक 12 वर्ष पूरे होने पर यूपी में मनेगा विकास का महापर्व, लखनऊ से वाराणसी तक सीएम योगी रहेंगे मौजूद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के ऐतिहासिक 12 वर्ष पूरे होने पर उत्तर प्रदेश में भव्य आयोजन होने जा रहे हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोकभवन में राजग (NDA) के सहयोगी दलों के साथ मीडिया संवाद करेंगे और विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही सीएम योगी नोएडा के लिए 45 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और शाम को वाराणसी में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे.

(जीएनएस)।

लखनऊः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के ऐतिहासिक 12 वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में एक भव्य उत्सव का आगाज होने जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार इस अवसर को 'विश्वास, विकास और जनकल्याण के गौरवपूर्ण 12 वर्ष' के रूप में पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाएगी. इस महा-आयोजन के तहत मुख्यमंत्री सुबह राजधानी लखनऊ और शाम को बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जहां वे मोदी सरकार के सुशासन, जनकल्याण और विकास यात्रा की बड़ी उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे.

मोदी सरकार के सुशासन के 12 वर्ष की उपलब्धियों को बताएगी योगी सरकार

सुशासन को समर्पित पीएम मोदी के द्वारा 140 करोड़ भारतीयों की निरंतर सेवा के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकभवन में मीडिया संवाद करेंगे. मोदी सरकार के नेतृत्व में जनकल्याण, अवस्थापना एवं आस्था को मिले सम्मान के विषय में संपूर्ण जानकारी भी देंगे. मोदी सरकार के 12 वर्षों की विकास यात्रा को लेकर यहां प्रदर्शनी भी लगेगी. इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे.

सरकार के साथ ही भाजपा संगठन व सहयोगी दल के नेता भी रहेंगे मौजूद

भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संगठन की तरफ से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष/केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी भी रहेंगे. साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश सरकार के मंत्री व सहयोगी दल अपना दल (एस) के आशीष पटेल, निषाद पार्टी के डॉ. संजय निषाद, सुभासपा के ओमप्रकाश राजभर व राष्ट्रीय लोकदल के अनिल कुमार भी रहेंगे.

PRGI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकार को कहा : बेईमान और बेववूफ

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्राध्यक्षों से तो बदतमीजी से पेश आते ही हैं पर अपने देश के पत्रकारों खासकर महिला पत्रकारों से वैसे पेश आते हैं ताजा घटना से पता चलता है। ट्रंप ने एनबीसी जैसी बड़ी टीवी नेटवर्व से एक इंटरव्यू के दौरान अचानक बातचीत बीच में ही खत्म कर दी। कार्यव्रम की होस्ट व्रिस्टन वेल्कर बार-बार उनके (ट्रंप के) कई दावों पर सवाल उठा रही थीं। रविवार को प्रसारित हुए कार्यव्रम 'मीट द प्रेस' में ट्रंप ने दावा किया कि वैलिफोर्निया में चल रहे प्राइमरी चुनाव और साल 2020 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव दोनों ही धांधली पूर्ण थे। जब वेल्कर ने चुनावों में धांधली के दावे के समर्थन में सुबूत मांगे तो ट्रंप ने कहा, 'मुझे बस देखना और सुनना भर है।' इस पर वेल्कर ने कहा यह सुबूत नहीं है। इसके बाद ट्रंप ने मीडिया पर बेईमान होने का आरोप लगाया और इंटरव्यू समाप्त करते हुए कहा, माफ कीजिए, अब इसे यहीं खत्म करते हैं। मेरे लिए बहुत हो गया यह इंटरव्यू अब खत्म है। इंटरव्यू शुरू होने के लगभग 50 मिनट बाद इसे छोड़ दिया। वेल्कर के सवालों के जवाब में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए कार्रवाई करनी जरूरी थी और यह अंतहीन युद्ध नहीं होगा। हम वहां वुछ महीनों के लिए रहेंगे और उसके बाद खतरा काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद बातचीत उस दंगे पर पहुंची और जब ट्रंप ने साल 2020 के चुनाव में धांधली का अपना पुराना, बिना सुबूत वाला दावा दोहराया तो व्रिस्टन वेल्कर ने उन्हें चुनौती दी। ट्रंप ने फिर वैलिफोर्निया के प्राथमिक चुनावों का जिव्र किया, जहां गवर्नर सहित कई पदों के लिए नवम्बर में होने वाले मध्यावधि चुनावों में कौन से दो उम्मीदवार होंगे। यह तय करने के लिए वोटों की गिनती जारी थी। उन्होंने फिर आरोप लगाया, वे चुनाव में धांधली कर रहे हैं, पलटकर वेल्कर ने पूछा : क्या आपके पास इसके समर्थन में कोई सुबूत है? ट्रंप : मुझे सिर्प देखना और सुनना है। वेल्कर ने बीच में टोका, लेकिन यह कोई सुबूत नहीं हैं। ट्रंप ने आगे कहा वे बेईमान हैं बिल्वुल आपकी तरह। इस पर वेल्कर ने जवाब दिया निष्पक्षता की बात करें तो मैं बेईमान नहीं हूं। लेकिन बातचीत जारी रखें, इस पर ट्रंप ने उनसे कहा या तो आप बेईमान हैं या फिर बेववूफ और यह कहते हुए ट्रंप उठ गए और कहा इसे यहीं खत्म करते हैं। मेरे लिए बहुत हो गया। शुव्रिया डार्लिंग, आपको अपने प्रेस को सुधारना चाहिए क्योंकि एक देश कभी महान नहीं बन सकता अगर उसकी प्रेस बेईमान है। हम इस महान पत्रकार को सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी बेइज्जती सही पर डटी रहीं।

क्या इजरायल अमेरिका की जासूसी कर रहा है?

ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप व इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच टकराव व बढ़ती रणनीतिक दूरियों ने पेंटागन की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय को इजरायली जासूसी का भय लगने लगा है। उसने चेतावनी दी है कि वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी कड़ी इजरायली निगरानी का निशाना बन सकते हैं? एनबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के दो मौजूदा व एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि पेंटागन की डिपैंस इंटेलिजेंस एजेंसी (डीआईए) ने हाल ही में इजरायल के लिए काउंटर इंटेलिजेंस खतरे के स्तर को व्रिटिकल यानी गंभीर कर दिया है। यह उनका सबसे ऊंचा आंतरिक मूल्यवान स्तर है। एक मौजूदा अधिकारी ने अमेरिकी पत्रकार को बताया कि अमेरिका पहले से ही इजरायल की आधिकारिक यात्राओं के दौरान सुरक्षा उपाय बरतता है क्योंकि इजरायली जासूसी एजेंसियों को जानकारी जुटाने के मामले में बहुत आव्रामक माना जाता रहा है। पेंटागन की नई चिंताओं से पता चलता है कि इजरायल पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के संबंध में अमेरिकी रणनीतिक चचाओं व पैसलों की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इजरायली जासूसी नेटवर्व खासकर उनकी खुफिया एजेंसी ऐसे कामों के लिए दुनिया में बदनाम है। चौंकाने वाली बात यह है कि मोसाद ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी अमेरिका को भी नहीं बक्शा है?

योगी सरकार ने एक्सप्रेसवे की अहम बॉडी छीनकर मुख्यमंत्री आफिस के कंट्रोल में क्यों की

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की प्रमुख एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण को उस विभाग में स्थानांतरित कर दिया है, जो सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन काम करता है. इसे राज्य की कुछ सबसे महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) को औद्योगिक विकास विभाग से हटाकर इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग के अधीन कर दिया गया है. औद्योगिक विकास विभाग का नेतृत्व मंत्री नंद गोपाल नंदी कर रहे थे. इस बदलाव के बाद सभी एक्सप्रेसवे परियोजनाएं और उनसे जुड़ी बुनियादी ढांचा योजनाएं सीधे मुख्यमंत्री की निगरानी में आ जाएंगी.

राज्य बीजेपी के पदाधिकारियों का मानना है कि यह फैसला नंदी के लिए एक झटका है. नंदी को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के करीब माना जाता है. नंदी ने इस फैसले पर आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से मुलाकात की.

उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास विभाग सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र या पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत चलने वाली बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की नीति बनाने और उनके समन्वय का काम करता है.

वढएक्ऊअ को इस विभाग के अधीन लाकर सरकार का उद्देश्य फैसले लेने की प्रक्रिया और परियोजनाओं के क्रियान्वयन को और तेज तथा सुचारु बनाना है.

दिप्रिंट ने नंदी से प्रतिक्रिया लेने के लिए फोन कॉल और संदेश के जरिए संपर्क किया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला. यदि उनकी प्रतिक्रिया मिलती है तो रिपोर्ट को अपडेट कर दिया जाएगा.

ऑर्डर में क्या लिखा है

सरकारी ऑर्डर के मुताबिक, इस बदलाव का मकसद काम के बंटवारे में दिक्कतों को खत्म करना और फाइलों का जल्दी निपटारा पक्का करना है.

अभी तक, वढएक्ऊअ प्रोजेक्ट से जुड़े बजट और अप्रूवल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जरिए प्रोसेस होते थे और मुख्यमंत्री तक पहुंचने से पहले कई लेवल पर क्लियरेंस की जरूरत होती थी. नए इंतजाम के तहत, उन्हें सीधे मुख्यमंत्री ऑफिस के जरिए भेजा जाएगा, अधिकारियों का मानना है कि इससे अप्रूवल में तेजी आएगी और लागू करने में देरी कम होगी.

सीएमओ के अधिकारियों का कहना है कि एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट एजेंडा के सबसे साफ निशानों में से हैं और इसलिए, इन पर ज्यादा नजर रखने की जरूरत है.

इन प्रोजेक्ट से जुड़े सीनियर अधिकारियों की पहले से ही मुख्यमंत्री तक सीधी पहुंच थी और वढएक्ऊअ को इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट के तहत लाने का मकसद स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी पहलों को तेजी से पूरा करना पक्का करना है.

इस कदम से सीएमओ द्वारा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की सीधी निगरानी को मजबूत करने की उम्मीद है और

यह सरकार की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के एक अहम हिस्से के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर को दिखाता है.

एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने दावा किया कि कुछ ह्लसीनियर अधिकारी मंत्री के साथ सहज नहीं थे, जिन्हें हर फाइल पर सवाल उठाने की आदत थी. इसलिए उट ने विकास के काम में तेजी लाने के पक्ष में फैसला किया. इसमें कुछ भी गलत नहीं है.ह्व

मंत्री और अधिकारियों के बीच तनाव

इस फैसले से मंत्री और अधिकारियों के कुछ हिस्सों के बीच अंदरूनी तनाव के बारे में भी अटकलें लगने लगी हैं. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सूत्रों ने कहा कि हाल के ट्रांसफर पर नंदी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आलोक कुमार के बीच असहमति की वजह से यह मामला हो सकता है.

खबर है कि यह विवाद मुख्यमंत्री के लेवल तक पहुंच गया था. वढएक्ऊअ में अधिकारियों के अपॉइंटमेंट और डेपुटेशन को लेकर भी सवाल उठाए गए, जिससे कई जानकारों ने इस नए एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव को उसी संदर्भ में देखा.

नंदी और उनके डिपार्टमेंट के सिविल सर्वेंट्स के बीच विवाद कोई नई बात नहीं है.

पिछले साल, मंत्री ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि सीनियर अधिकारी मंत्री के निर्देशों को नजरअंदाज कर रहे हैं और अपने पसंदीदा लोगों को गलत फायदे पहुंचा रहे हैं. नंदी ने सीनियर अधिकारियों पर यह भी आरोप लगाया कि वे अपनी मर्जी से फैसले ले रहे हैं, तय पॉलिसी और प्रोसेस को नजरअंदाज कर रहे हैं, और यहां तक कि ऑफिशियल फाइलें और रिकॉर्ड भी गायब होने दे रहे हैं.

सूत्रों के मुताबिक, नंदी और वढएक्ऊअ लीडरशिप के बीच तनाव मनोज कुमार सिंह के समय से है, जो अभी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के हेड हैं. मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले सिंह पहले वढएक्ऊअ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) रह चुके हैं.

सूत्रों ने बताया कि सिंह के रिटायरमेंट और दीपक कुमार के अथॉरिटी के नए सीईओ बनने के बाद भी मतभेद बने रहे.

इस मामले से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, नंदी के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की देखरेख कर रहे सीनियर सिविल सर्वेंट्स के साथ रिश्ते बेहतर नहीं हुए, और शायद यही उन वजहों में से एक था जिसने वढएक्ऊअ का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बदलने के फैसले पर असर डाला.

पहले, ऐसे झगड़ों का शायद ही कोई बड़ा नतीजा निकला हो.

राज्य सरकार को अक्सर विपक्षी पार्टियों और यहां तक कि अपने ही रैंक के लोगों से भी आलोचना का सामना करना पड़ा है कि कथित तौर पर सिविल सर्वेंट्स के हाथों में बहुत ज्यादा पावर जमा कर दी गई है.

मंत्रियों और विधायकों ने अक्सर शिकायत की है कि अधिकारी चुने हुए प्रतिनिधियों को नजरअंदाज करते हैं और योगी आदित्यनाथ सरकार के दोनों कार्यकालों के दौरान ऐसे कई टकराव सामने आए हैं.

2022 में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने अपने ही डिपार्टमेंट के अधिकारियों से सबके सामने नाखुशी जताई और उनके काम करने के तरीके की शिकायत करते हुए फॉर्मल लेटर लिखे. एक बार तो ऐसा भी हुआ कि उन्होंने एक ऑफिशियल परफॉर्मेंस असेसमेंट के दौरान एक ऑफिसर को खराब रेटिंग देकर अपनी नाराजगी जाहिर की.

उसी साल एक और बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देने की पेशकश करते हुए चिट्ठी लिखी. खटीक ने आरोप लगाया कि अधिकारी उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे क्योंकि वह दलित समुदाय से थे और उन्होंने दावा किया कि उन्हें जरूरी डिपार्टमेंटल मीटिंग में भी नहीं बुलाया जाता था.

इस घटना से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सभी राज्य मंत्रियों को खास डिपार्टमेंटल ज़िम्मेदारियां दी जाएं. बीजेपी लीडरशिप के दखल के बाद ही मामला शांत हुआ.

तब से, कम से कम नौ मंत्रियों के लेटर कथित तौर पर लीक हो चुके हैं, जिनमें से कई ने ऑफिसरों की कथित बेपरवाही या उनके काम करने के तरीके की आलोचना करने पर चिंता जताई है.

राज्य सरकार ने सिविल सर्वेंट्स को कम से कम 15 रिमाइंडर जारी किए, जिसमें उन्हें सही व्यवहार बनाए रखने और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का पूरा सम्मान करने का निर्देश दिया गया.

कई मंत्रियों ने प्राइवेट तौर पर भी शिकायत की है कि उनके डिपार्टमेंट के काम में चीफ मिनिस्टर ऑफिस बहुत ज्यादा दखल देता है, यह चिंता सरकार के दोनों टर्म में बनी रही है.

'प्रोजेक्ट गंगा'.. समझिए कैसे रोजगार के साथ बदलेगी यूपी के 57 हजार ग्राम पंचायतों की तस्वीर

(जीएनएस)।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना 'प्रोजेक्ट गंगा' की शुरूआत कर दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रदेश का नया 'डिजिटल एक्सप्रेसवे' बताया. सीएम योगी ने मंगलवार को इस परियोजना का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट गंगा डिजिटल समावेशन को नई गति देगा और गांवों में स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करेगा. इस योजना के तहत हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा.

प्रोजेक्ट गंगा के जरिए प्रदेश के लगभग 20 लाख परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. इसके साथ ही 8 से 10 हजार डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर को तैयार किया जाएगा, जिससे एक लाख से ज्यादा युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा. परियोजना के पहले चरण में 21 जिलों में काम शुरू हो रहा है. आगे इसे पूरे प्रदेश की लगभग 57 हजार ग्राम पंचायतों और करीब 8 हजार न्याय पंचायतों तक विस्तारित किया जाएगा. इससे गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने में मदद मिलेगी.

सीएम योगी का बयान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी आज की जरूरत बन चुकी है. जितनी तेज इंटरनेट सुविधा होगी, विकास की रफ्तार भी उतनी ही तेज होगी. उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'डिजिटल इंडिया' मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया. सीएम ने मां गंगा की उपमा देते हुए कहा कि जिस तरह गंगा विकास और समृद्धि का आधार रही है, उसी तरह प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश की डिजिटल समृद्धि का मजबूत आधार बनेगा. इससे डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने हिंदुजा ग्रुप को इस पहल के लिए बधाई दी. उन्होंने बताया कि 'सीएम युवा' योजना के तहत चयनित युवाओं को 5 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे डिजिटल सेवा प्रदाता के रूप में अपना उद्यम शुरू कर सकें. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने भी इस परियोजना को प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ी पहल बताया. यह योजना उत्तर प्रदेश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.

महुआ मोइत्रा को 'इश्क करो पार्टी' में क्यों देखना चाहते हैं 80 साल के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज? असली गेम प्लान क्या?

(जीएनएस)।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने 80 साल की उम्र में अचानक एक नई 'पार्टी' लॉन्च कर दी। नाम है 'इश्क करो पार्टी'। नारा है, 'युद्ध नहीं, प्रेम करो'। सुनने में यह कोई रोमांटिक या मजाकिया आइडिया लग सकता है, लेकिन इसके पीछे उनका क्या असली इरादा है? और वे तृणमूल कांग्रेस की फायरब्रांड नेता महुआ मोइत्रा को इसमें क्यों देखना चाहते हैं?

क्या यह सचमुच कोई नई राजनीतिक शुरूआत है या सिर्फ एक तेज धार वाला राजनीतिक व्यंग्य? इस पूरे एपिसोड को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि 'इश्क करो पार्टी' वास्तव में है क्या, इसका संदेश क्या है, महुआ मोइत्रा का जिक्र क्यों हो रहा है, और काटजू का असली गेम प्लान किस दिशा में जाता दिखता है।

इश्क करो पार्टीः नाम रोमांटिक, एजेंडा राजनीतिक

मार्कंडेय काटजू ने 'इश्क करो पार्टी' को एक मंच के रूप में पेश किया है, जो उनके मुताबिक, भारत में राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और आम लोगों की बुनियादी समस्याओं पर जनसंघर्ष खड़ा करने के लिए बनाया गया है।

उन्होंने अपने दोस्त इरफान अली (जो अमेरिका के न्यू जर्सी, प्रिंसटन में रहते हैं) के साथ मिलकर यह प्लेटफॉर्म खड़ा किया। इरफान ने तुरंत इसके लिए वेबसाइट, इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट और एक आधिकारिक ईमेल आईडी -- बना दी। खुद काटजू इस मंच के 'संरक्षक' की भूमिका में हैं, जबकि इरफान अली को 'अध्यक्ष'बताया गया है। काटजू साफ कह चुके हैं कि यह कोई पारंपरिक चुनावी राजनीतिक पार्टी नहीं है। वे इसे ऐसे मंच के रूप में देखते हैं जोः देशभक्त और जागरूक नागरिकों को जोड़े - धर्मनिरपेक्ष, आधुनिक और वैज्ञानिक सोच वाले नेतृत्व को सामने लाए - जाति-धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर जनदबाव बनाए डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया को इस 'पार्टी' का मुख्य मैदान बनाया गया है। यही वजह है कि इसका पहला औपचारिक एलान भी (पूर्व ट्विटर) और ईमेल के जरिए किया गया।

जस्टिस काटजू ने यह मंच अभी क्यों शुरू किया?

काटजू के मुताबिक, भारत इस समय बेहद गंभीर संकटों से जूझ रहा है। वे जिन मुद्दों को सबसे बड़े संकट के रूप में देखते हैं, वे हैं... व्यापक गरीबी और बेरोजगारी बच्चों में कुपोषण का खतरनाक स्तर (ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसे इंडिकेटर्स का हवाला देकर वे कहते हैं कि हर दूसरा बच्चा किसी न किसी रूप में प्रभावित है)। आम जनता के लिए स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की भारी कमी। महंगाई, खासकर रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें। जाति और धर्म के नाम पर नफरत और हिंसा।

काटजू का तर्क है कि इन समस्याओं से निपटने के लिए भारतीय समाज को एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन, उनके अनुसार, मौजूदा राजनीतिक ढांचा और बड़े-बड़े नेता लोगों को जाति, धर्म, भाषा और नस्ल के आधार पर बांटने में लगे हैं। यहीं से 'इश्क करो पार्टी' का आइडिया आता है। उनकी नजर में यह एक ऐसा मंच है जो विभाजन और नफरत की राजनीति के खिलाफ 'दिल' और 'दिमाग' दोनों स्तर पर प्रतिरोध खड़ा करे और लोगों को बतौर नागरिक जोड़ने की कोशिश करे।

यह 'इश्क' कौन-सा है? सूफी अर्थ बनाम रोमांटिक गलतफहमी

'इश्क-ए-हकीकी' का मतलब है ईश्वर से, या किसी उच्च आदर्श से वह प्रेम, जिसके लिए इंसान अपना सब कुछ कुर्बान कर सके। यह ऐसा भाव है जो सीमाओं से परे है, न जाति, न धर्म, न भाषा, न नस्ल - कुछ भी आड़े नहीं आता।

काटजू अक्सर मिर्जा गालिब के शेर का उदाहरण देते हैं:

'इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश 'गालिब' कि लगाए न लगे और बुझाए न बने!'

उनका कहना है कि 'इश्क करो पार्टी' में 'इश्क' का मतलब है - देश के हर नागरिक के लिए प्रेम, मानवीय करुणा और बराबरी की भावना। यानि एक तरह का राजनीतिक और सामाजिक 'सूफी इश्क', जो विभाजन की जगह एकता पर जोर देता है।

'इश्क करो पार्टी' की एंट्री ऐसे समय में हुई, जब एक और डिजिटल-युग की 'व्यंग्यात्मक' पार्टी पहले से सुर्खियों में थी 'कॉकरोच जनता पार्टी'। कॉकरोच जनता पार्टी (उखढ) के संस्थापक अभीजित दीपके हाल के दिनों में दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर चुके हैं। यह 'पार्टी' खुद को एक तंजिया, लेकिन राजनीतिक तौर पर एंगेज्ड प्लेटफॉर्म के रूप में पेश कर रही है और उसने काफी हद तक त्र्ह्ल्ल` और युवा सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा है। उनका प्लान है कि अपनी मांगों और विरोध-प्रदर्शनों को राज्यस्तर पर पूरे देश में फैलाया जाए।

इसी बीच, काटजू ने 'इश्क करो पार्टी' की घोषणा की। वे खुलकर कह रहे हैं कि युवा, खासकर त्र्ह्ल्ल`, आज एक ऐसे माहौल में बड़े हो रहे हैं जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म राजनीति पर हावी हैं। हेट स्पीच और ध्रुवीकरण सामान्य बात बन चुके हैं। जोश बहुत है, पर दिशा कई बार भटक जाती है। काटजू खुद को युवाओं के लिए एक वैकल्पिक 'पथप्रदर्शक' के रूप में पेश करते हैं और कहते हैं कि 'युद्ध नहीं, प्रेम करो' सिर्फ स्लोगन नहीं, बल्कि राजनीति में 'ूमैनिटी और नैतिकता वापस लाने का संदेश है।

असली गेम प्लानः पार्टी या पॉलिटिकल व्यंग्य?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या काटजू सचमुच कोई गंभीर राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं, या यह उनके पहले के प्रयोगों की तरह एक तीखा व्यंग्य है?

वे पहले 'कॉकरोच जनता पार्टी' जैसी कल्पित पार्टी का जिक्र कई बार कर चुके हैं, जहां वे भ्रष्ट, अवसरवादी राजनीति पर तंज कसते थे। 'इश्क करो पार्टी' भी बहुत हद तक उसी सिलसिले की अगली कड़ी लगती है, लेकिन इस बार फोकस केवल तंज पर नहीं, बल्कि एक 'पॉजिटिव' वैल्यू यानी प्रेम और एकता पर रखा गया है। डिजिटल युग में जहां हर चीज कंटेंट, मीम और ट्रेंड में बदल जाती है, काटजू का असली दांव यही लगता है कि वे गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए व्यंग्य और प्रतीकवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। 'पार्टी' का फॉर्मेट चुनकर वे दिखाना चाहते हैं कि अगर नफरत की राजनीति पार्टी बन सकती है, तो 'इश्क' भी एक राजनीतिक विचार बन सकता है।

इस पूरी कहानी का सबसे चर्चित हिस्सा वह स्क्रीनशॉट है, जो सोशल मीडिया पर घूमता रहा। उसमें दावा किया गया कि काटजू ने महुआ मोइत्रा को 'इश्क करो पार्टी' में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। यह बात तुरंत सुर्खियों में इसलिए आ गई क्योंकि महुआ मोइत्रा अपनी आक्रामक, बेलौस और तीखी राजनीतिक शैली के लिए जानी जाती हैं। संसद और टीवी डिबेट्स में उनके भाषण अक्सर सरकार पर सीधे, कटु और धारदार हमले माने जाते हैं।

'इश्क करो पार्टी' को समझने के लिए काटजू की पर्सनैलिटी और बैकग्राउंड पर एक नजर डालना जरूरी है, क्योंकि वही इस पूरे प्रयोग का टोन सेट करती है। 20 सितंबर 1946 को जन्मे मार्कंडेय काटजू कानून की गहरी परंपरा वाले परिवार से आते हैं। उनके पिता एस.एन. काटजू इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। उनके दादा डॉ. कैलाश नाथ काटजू आजादी की लड़ाई में सक्रिय रहे, आजाद भारत में केंद्रीय गृह और रक्षा मंत्री रहे, और एक बड़े राजनेता व वकील माने जाते थे।

डिजिटल प्रोवोकेशनः उम्र 80, अंदाज पूरी तरह ऑनलाइन

काटजू की मौजूदा रणनीति को अगर एक वाक्य में समझना हो तो वह है - 'डिजिटल प्रोवोकेशन'। वे (पूर्व ट्विटर), फेसबुक और ब्लॉग्स के जरिए ऐसी बातें लिखते हैं, जो तुरंत बहस, ट्रोलिंग और वायरल कंटेंट बन जाएं। वे पारंपरिक राजनीतिक दल बनाने या चुनाव मैदान में उतरने की दिशा में नहीं दिखते, लेकिन राजनीतिक विमर्श को झकझोरते रहने की चिंता लगातार दिखती है। 'इश्क करो पार्टी' उनके इसी डिजिटल एजेंडा का नया एपिसोड है, जिसमें वे नफरत भरे नेरेटिव के बीच अचानक 'प्रेम करो' जैसी बात उछालकर सबको असहज कर देते हैं।

अपना संविधान, अपनी पुलिस, अपनी सरकार, फिर भी इस्लामाबाद के इशारों पर क्यों चलता है पीओके?

(जीएनएस)।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। खअअउ ने 9 जून को मुजफ्फराबाद और रावलकोट में प्रदर्शन शुरू किया था, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। इन घटनाओं ने एक बार फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजनीतिक और संवैधानिक स्थिति को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ढङ्कङ्ग का अपना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा, संविधान और यहां तक कि अलग झंडा भी है। लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र पर वास्तविक नियंत्रण इस्लामाबाद और पाकिस्तान की सत्ता संरचना के हाथों में माना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह व्यवस्था बनी कैसे और पाकिस्तान इसे क्यों बनाए रखना चाहता है?

ढङ्कङ्ग की शुरूआत कैसे हुई?

आज जिस क्षेत्र को भारत, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (PoK) कहता है, उसका इतिहास 1947 के भारत-विभाजन से जुड़ा हुआ है। यह लगभग 13,297 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जिस पर पाकिस्तान का कंट्रोल है। पाकिस्तान इसे "आजाद जम्मू-कश्मीर" कहता है, जबकि भारत इसे अपने जम्मू-कश्मीर का अवैध रूप से कब्जाया गया हिस्सा मानता है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित पश्तून कबायली लड़ाकों ने जम्मू-कश्मीर पर हमला किया था। उस समय जम्मू-कश्मीर एक रियासत थी, जिसके शासक महाराजा हरि सिंह थे। विभाजन के बाद उन्होंने तत्काल भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला नहीं किया था।

लेकिन जैसे-जैसे कबायली हमलावर श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे, महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अगले ही दिन भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची और पाकिस्तान तथा भारत के बीच पहला युद्ध शुरू हो गया। करीब 14 महीने तक चले इस युद्ध के बाद 31 दिसंबर 1948 की रात युद्धविराम लागू किया गया। 1 जनवरी 1949 से युद्धविराम रेखा प्रभावी हुई, जिसके बाद जम्मू-कश्मीर का लगभग 13,297 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान के कंट्रोल में रह गया।

आज पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इस क्षेत्र को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा तथाकथित "आजाद जम्मू-कश्मीर" (AJK) है और दूसरा गिलगित-बाल्टिस्तान (GB)। गिलगित-बाल्टिस्तान अकेले PoK के कुल क्षेत्रफल का लगभग 86 प्रतिशत हिस्सा बनाता है। भारत का आधिकारिक रुख यह है कि PoK और गिलगित-बाल्टिस्तान दोनों ही 1947 में हुए विलय के आधार पर भारत का अभिन्न हिस्सा हैं।

PoK का प्रशासन 1974 के "आजाद जम्मू-कश्मीर अंतरिम संविधान अधिनियम" के तहत संचालित होता है। इसी व्यवस्था के आधार पर वहां अलग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा, न्यायिक प्रणाली और पुलिस बल मौजूद हैं। 1974 के इस अंतरिम संविधान और पाकिस्तान के संविधान के कुछ प्रावधान मिलकर यह तय करते हैं कि PoK और इस्लामाबाद के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार होगा। कागजों पर देखने पर ऐसा लगता है कि PoK को काफी हद तक स्वायत्तता या स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वास्तविक फैसले लेने की शक्ति अभी भी पाकिस्तान के केंद्रीय नेतृत्व के पास ही रहती है।

लखनऊः पेपर लीक के खिलाफ 12 जून को सड़क पर उतरेंगे छात्र, कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके भी होंगे शामिल

लखनऊ के इको गार्डन में 12 जून को पेपर लीक को लेकर युवा आक्रोश प्रदर्शन होगा। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (अक्सअ) की ओर से होने वाले इस प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके शामिल होंगे।

(जीएनएस)।

लखनऊः लखनऊ के इको गार्डन में 12 जून को पेपर लीक को लेकर युवा आक्रोश प्रदर्शन होगा। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की ओर से होने वाले इस प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके शामिल होंगे।

अभिजीत ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करते हुए प्रदर्शन में शामिल होने की सूचना दी है। उन्होंने

कहा कि 12 जून को हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पेपर लीक के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे हैं। सभी लोगों से अपील है कि वहां आकर छात्रों का साथ देते हुए इस लड़ाई में शामिल हों। अपनी वीडियो में अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचकर पेपर लीक के खिलाफ आवाज को मजबूत करें।

AISA की तरफ से प्रदर्शन का किया गया आह्वान

युवा आक्रोश प्रदर्शन का आह्वानऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की तरफ से किया गया है। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके लखनऊ पहुंचेंगे, ईको गार्डन में आयोजित इस प्रदर्शन में शामिल होंगे अभिजीत, ठएएळ पेपर लीक के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन होगा। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उठेगी।

12 तारीख को होने वाले प्रदर्शन की 4 प्रमुख मांगें हैं। पेपर लीक की निष्पक्ष जांच हो दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित हो। युवाओं को रोजगार की गारंटी दी जाए।

दान से चले कॉलेज अब खतरे में, लखनऊ में 7 सहायता प्राप्त संस्थानों की जमीन हथियाने की कोशिशें; बड़ा खुलासा

(जीएनएस)।

लखनऊ, लखनऊ के कई सहायता प्राप्त विद्यालयों और कॉलेजों की जमीनों पर कब्जे के प्रयासों का मामला सामने आया है। रिपोर्ट में शिक्षा विभाग, प्रबंधन और बाहरी प्रभावशाली लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। कई पुराने शैक्षणिक संस्थानों को कानूनी विवादों और कथित अवैध कब्जों से बचाने की मांग तेज हो गई है।

कभी दान से खुले राजधानी के एडेड कॉलेजों का वजूद अब खतरे में है। विद्यालयों में कभी जर्जर, कभी प्रबंधन समिति के झगड़े, तो कभी मालिकाना हक को लेकर कब्जे का प्रयास होता रहा है। अभी तक लखनऊ में सात सहायता प्राप्त कॉलेजों की जमीनों को हथियाने का प्रयास हुआ है, लेकिन इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से कोई मजबूत कदम नहीं उठाया गया।

विद्यालय की जमीन कब्जाने में मंत्री, माफिया और प्रबंधकों का गठजोड़ भी सामने आ चुका है। कई बार शिक्षा विभाग के बाबुओं और अधिकारियों की भी मिलीभगत से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसके सबसे बड़े उदाहरण लखनऊ इंटर कॉलेज, सरस्वती कन्या इंटर कॉलेज, सेंटीनियल इंटर कॉलेज, एडेड जूनियर हाईस्कूल लालबाग, चुटकी भंडार इंटर कॉलेज रहे हैं और अब नरही स्थित विद्या मंदिर गर्ल्स हाईस्कूल भी निशाने पर था।

जानें, क्या कहता है अधिनियम

अधिनियम में तीन बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्था का प्रबंधन अपनी संपत्ति को किसी को देना चाहती है तो विभाग के निदेशक से मंजूरी लेनी होगी। निदेशक यह मंजूरी तभी देगा, जब ये साबित हो कि संपत्ति को बेचना या देना संस्था के भले के लिए है।

अधिनियम में स्पष्ट है कि कोई भी दूसरा कानून या नियम इस बात को नहीं बदल सकता। निदेशक की लिखित मंजूरी के बिना किया गया ऐसा कोई भी लेनदेन कानूनी रूप से अमान्य होगा।

विद्या मंदिर गर्ल्स हाईस्कूल के मामले में सामने आई इनकी लापरवाही

प्रबंधकः 21 अप्रैल को जब प्रबंधक संतोष रस्तोगी को विद्यालय खाली करने का आदेश मिला तो विभाग को सूचना क्यों नहीं दी? वकील के साथ-साथ केस की स्थिति स्वयं क्यों नहीं समझी।

एडीएम : जब सरकार से सहायता प्राप्त संस्था के भवन को किसी के पक्ष में कब्जा देने का आदेश दिया तो उससे पहले संस्था से जुड़े विभाग को क्यों नहीं तलब कर पक्ष जाना? साथ ही विद्यालय से जुड़े अधिनियम को क्यों दरकिनार किया? निदेशक का अनुमोदन जरूरी होता है, बिना अनुमोदन विद्यालय खाली करने का आदेश कैसे दिया गया?

शिक्षा विभाग : प्रबंधक का दावा है कि तत्कालीन डीआईओएस को घटना की सूचना दी गई थी। इसके बाद भी विभाग ने संज्ञान नहीं लिया। विभागीय निरीक्षण में लापरवाही क्यों हुई? सहायता प्राप्त कॉलेजों में निरीक्षण की व्यवस्था के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया। यदि समय पर निरीक्षण होता विद्यालय की स्थिति पता चलती।

शिक्षा विभाग और प्रबंधकों का गठजोड़ सामने आया

माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के प्रादेशीय मंत्री डॉ. आरपी मिश्रा ने बताया कि 6 यदि सरकार ने समय रहते एडेड कॉलेजों की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाया तो इन कॉलेजों पर एक दिन माफिया का कब्जा हो जाएगा और गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। अभी तक सात-आठ संस्थानों की जमीनें कब्जाने का प्रयास हो चुका है। इसमें माफिया, शिक्षा विभाग और प्रबंधकों का गठजोड़ सामने आया है।

लखनऊ इंटर कॉलेज, लालबाग

करीब 10 साल पहले हजरतगंज स्थित लखनऊ इंटर कॉलेज को एडीएम कोर्ट के आदेश पर जर्जर बताते हुए गिराने की कोशिश हुई। देर रात 150 दबंगों ने विद्यालय में घुसकर हथौड़ा चलाया तो तत्कालीन डीआईओएस मुकेश कुमार गेट पर ही कुर्सी डालकर बैठ गए थे, तब माफिया भागे।

एडेड जूनियर हाई स्कूल, लालबाग

सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे नटवर गोयल पर स्कूल कब्जाने का केस 2 आरोप लगा। जिस स्कूल को गिराकर वहां नवनिर्माण किया जा रहा था, मौके पर पहुंचे पत्रकारों पर भी हमले का प्रयास हुआ था। इसके बाद नटवर गोयल को पुलिस ने पकड़ा और सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा भी छीन लिया।

लखनऊ के गौतमपल्ली की क्रिश्चियन कॉलोनी के ब्यूटी पार्लर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने दो लोगों को किया रेस्क्यू

(जीएनएस)।

लखनऊ। ब्यूटी पार्लर में शार्ट सर्किट से लगी आग ने मकान को अपनी जद में ले लिया। गौतमपल्ली थाना क्षेत्र की क्रिश्चियन कालोनी में गुरुवार सुबह एक मकान में संचालित ब्यूटी पार्लर में आग लग गई।

आग की लपट व धुएं के बीच दो लोग फंस गए। चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने दमकल को सूचना दी। आग की सूचना पर दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान चलाकर छत पर धुएं से घिरे दो लोगों को सीढ़ी की मदद से सुरक्षित नीचे उतार लिया। आग लगने के समय दो लोग भवन के अंदर फंस गए थे। दमकल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को लोहे की सीढ़ी के माध्यम से सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, जिससे आग आसपास के हिस्सों में फैलने से बच गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि, आग लगने के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। आग से हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है।

गौतमपल्ली की क्रिश्चियन कॉलोनी में 'जस्ट फॉर डिवाइस' केडीए ब्यूटी पार्लर में आग लगने की प्रारंभिक जांच में कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि पार्लर में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। मकान मालिक के मुताबिक आग तो भूतल पर संचालित पार्लर में लगी थी। पार्लर की संचालिका दीपिका राठौड़ हैं। आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन पार्लर में रखा सामान जल गया।

कांग्रेस ने पंजाब के राजनीतिक मूल्यांकन के लिए अजय माकन, मीनाक्षी नटराजन और भजन लाल जाटव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया

(जीएनएस)।

कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में राजनीतिक माहौल का मूल्यांकन करने के लिए अजय माकन, मीनाक्षी नटराजन और भजन लाल जाटव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। यह निर्णय कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल द्वारा राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अफवाहों को खारिज करने के बाद आया है। उन्होंने पुष्टि की कि आगामी विधानसभा चुनाव पार्टी नेताओं के सामूहिक प्रयास होंगे।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की, जिन्हें पंजाब की राजनीतिक स्थिति पर तत्काल रिपोर्ट प्रदान करने का काम सौंपा गया है। यह घोषणा 2 जून को खरगे के आवास पर हुई एक बैठक के तुरंत बाद की गई, जिसमें पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल सहित प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं।

पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में संभावित बदलावों के बारे में मीडिया अटकलों को संबोधित करते हुए, बघेल ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने एकता के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, कहा, "कांग्रेस सभी को साथ लेकर चलती है। हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे।" उन्होंने दोहराया कि नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा।

बघेल ने यह भी पुष्टि की कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के प्रमुख बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी राज्य चुनाव खरगे और गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जिसमें राज्य नेतृत्व के सामूहिक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

पंजाब में अगले साल की शुरूआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी की रणनीति आगामी चुनावी चुनौती के लिए तैयारी करते हुए अपने रैंकों के भीतर स्थिरता और एकता बनाए रखने पर केंद्रित प्रतीत होती है।

16 करोड़ घरों में नल से जल और 12 करोड़ शौचालय, पीयूष गोयल ने लखनऊ में पेश किया सुशासन का रिपोर्ट कार्ड

(जीएनएस)।

लखनऊः केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष भारत के लिए विकास, विश्वास और जन कल्याण का सबसे सुनहरा दौर रहा है. लखनऊ के सहकारिता भवन हजरतगंज में हुए 'विकसित भारत संकल्प सम्मेलन' में उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यकाल देश के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा. इस भव्य कार्यक्रम में पीयूष गोयल के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. नीरज सिंह, लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक और प्रबुद्धजन उपस्थित रहे.

वाणिज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने पर जताया आभारः केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों का सहृदय आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अवसर उनके लिए व्यक्तिगत रूप से बेहद विशेष है. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि जनसंघ के आदर्श डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनकी मूल संस्था के संस्थापक रहे और आज उन्हें उसी वाणिज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने का गौरव मिला है. पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्षों के बेमिसाल कार्यकाल की सराहना करते हुए बताया कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह अब तक का सबसे प्रभावशाली और लंबा कार्यकाल साबित हुआ है. उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि इन पिछले 4400 दिनों में देश की आम जनता की सक्रिय भागीदारी से भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया है.

4400 दिनों में देश ने छुई नई ऊंचाइयां.

बिना एक दिन की छुट्टी लिए पीएम ने की देश की सेवाः आने वाले अक्टूबर महीने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और मुख्यमंत्री के रूप में संवैधानिक पदों पर कुल 25 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे. अपने इस लंबे राजनीतिक और प्रशासनिक सफर के दौरान वे पिछले 25 वर्ष से बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए पूरी तरह से देश सेवा में समर्पित रहे. उन्होंने आगे कहा कि आज देश जिस मजबूत स्थिति में है, उसके पीछे प्रधानमंत्री की करीब 55 वर्ष की अनवरत राष्ट्रव्यापी तपस्या रही है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक निष्ठावान स्वयंसेवक के रूप में, फिर एक कुशल राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उनका जीवन हमेशा देश को समर्पित रहा.

लखनऊ के हजरतगंज में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल की सराहना की.

आर्थिक मंदी और युद्ध के बीच भारत ने रखी मजबूत नींवः देश में लगी इमरजेंसी के खिलाफ कड़ा संघर्ष हो या फिर पूर्व में कश्मीर के लाल चौक पर जाकर साहस के साथ तिरंगा फहराने की बात, उन्होंने हर राष्ट्रहित के कार्य में अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया. गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के बाद साल 2014 में वे उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी से सांसद चुने गए और तब से पूरे देश को विकास की नई राह पर ले जा रहे हैं. गोयल ने आर्थिक मोर्चे पर बात करते हुए कहा कि पश्चिमी देशों में चल रहे युद्ध और दुनिया भर में मची उथल-पुथल के बावजूद भारत ने अपनी बेहद मजबूत आर्थिक नींव रखी है. पिछले कुछ वर्षों में देश के कोने-कोने में विश्वस्तरीय आधारभूत बुनियादी सुविधाएं विकसित की गईं और देश को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नया तथा दूरदर्शी दृष्टिकोण दिया गया.

कोविड महामारी में 250 करोड़ वैक्सीन लगाने का रिकॉर्डः भयानक कोविड महामारी के कठिन समय को याद करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तब प्रधानमंत्री का एकमात्र दृढ़ संकल्प था कि संकट के इस दौर में देश का कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा. इसी संकल्प के तहत भारत ने रिकॉर्ड समय में स्वदेशी तकनीक से 250 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज लगाईं और बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को इसे मुफ्त में उपलब्ध कराया. केंद्र सरकार की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि देश के 16 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों तक पाइपलाइन के जरिए 'नल से जल' पहुंचाया जा चुका है. इसके साथ ही देश की माताओं-बहनों के सम्मान के लिए 12 करोड़ से अधिक 'इज्जत घर' (शौचालयों) का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है.

सुशासन और ईमानदारी से विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसरः इसके अलावा, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत के तहत देश के करोड़ों गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की बेहतरीन सुविधा दी जा रही है. इस सम्मेलन में उपस्थित सभी वरिष्ठ नेताओं और प्रबुद्धजनों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रेरणादायी नेतृत्व में देश को आने वाले समय में एक महान विश्व शक्ति बनाने के सामूहिक संकल्प को दोहराया. अंत में उन्होंने जोर देकर कहा कि आज का भारत केवल और केवल सुशासन, पूरी तरह से ईमानदार सरकार और जन कल्याण की सच्ची भावना के दम पर ही लगातार आगे बढ़ रहा है.

पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने दी बधाई, पोस्ट में ममता बनर्जी को किया टैग

(जीएनएस)।

नई दिल्ली, पीएम नरेंद्र मोदी ने मई 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी उनके नेतृत्व में एनडीए को जीत मिली और वह लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित रहने का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उनकी इस उपलब्धि पर राजनीति, सामाजिक और विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व की सराहना कर रही हैं. इसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं दी हैं.

शत्रुघ्न सिन्हा ने गुरुवार (11 जून, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना की. शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'खेल भावना के साथ, समाज और देश के हमारे मित्र और मार्गदर्शक, माननीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं. यह शायद अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है. आपके उज्ज्वल भविष्य, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करता हूं. जय हिंद.' उन्होंने अपने पोस्ट में यशवंत सिन्हा, ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी टैग किया.

शत्रुघ्न सिन्हा का पोस्ट काफी चर्चा में है, क्योंकि वह वर्तमान में विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं. ऐसे में राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री को दी गई उनकी शुभकामनाओं को सकारात्मक राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. इसके बाद वर्ष 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को जीत मिली और वह लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने. इस दौरान उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहलों का नेतृत्व किया और भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करने की दिशा में काम किया.

प्रधानमंत्री के लंबे कार्यकाल और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से लगातार जनादेश प्राप्त करने को भारतीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. उनके इस रिकॉर्ड पर देशभर से बधाइयों का सिलसिला जारी है. दरअसल टीएमसी के 19 सांसदों ने काकोली घोष को अपना नेता और एनडीए को समर्थन करने के लिए लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है इस लिस्ट में आसनसोल लोकसभा सीट से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी शामिल है.

शत्रुघ्न सिन्हा 1980 के दशक से भाजपा में सक्रिय रहे. 2019 में वह भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए. इसके बाद मार्च 2022 में कांग्रेस का दमन छोड़कर वह टीएमसी में शामिल हुए और आसनसोल लोकसभा का उपचुनाव जीता. इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक बार फिर भाजपा प्रत्याशी को 3 लाख से ज्यादा मतों से हराया.

कंगना रनौत ने की पूजा-अर्चना, पीएम मोदी के दीर्घायु होने की कामना की

(जीएनएस)।

जोधपुर, भाजपा सांसद कंगना रानौत ने कहा कि भारत आज दुनिया में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है और आने वाले समय में देश नई ऊंचाइयों को छुए, यही उनकी कामना है.

हिंदी सिनेमा जगत की जानी-मानी अभिनेत्री और लोकसभा में भाजपा सांसद कंगना रनौत गुरुवार (11 जून, 2026) को राजस्थान के जोधपुर के दौरे पर पहुंचीं. अपने दौरे के दौरान उन्होंने शहर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की. इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार के 12 साल पूर्ण होने पर भगवान का आभार जताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की.

मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 12 साल पूरा होना देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेवा करते हुए एक अलग पहचान बनाई है और उनके नेतृत्व में भारत लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है. कंगना ने कहा कि सरकार की स्थिरता और देश की प्रगति के लिए उन्होंने मंदिर में प्रार्थना की है. उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है और आने वाले समय में देश नई ऊंचाइयों को छुए, यही उनकी कामना है. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान समय में देश और दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है. ऐसे में मजबूत नेतृत्व देश के लिए बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु देश के हित में है. जोधपुर पहुंचने पर कंगना रनौत के समर्थकों में भी उत्साह देखने को मिला. मंदिर परिसर में उनके पहुंचने की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में लोग वहां जुटे।

पूर्व पति द्वारा सोशल मीडिया पर धूम्रपान को बढ़ावा देने के आरोपों के बाद महिला ने बेटे की हिरासत की मांग की

(जीएनएस)।

पुलिस रिपोर्टों के अनुसार, लोहियानगर की एक महिला ने अपने पूर्व पति पर अपने आठ वर्षीय बेटे को सिगरेट पीने के लिए प्रोत्साहित करने और सोशल मीडिया के लिए बच्चे के वीडियो रिकॉर्ड करने का आरोप लगाया है। महिला, गजाला, का दावा है कि उसका बेटा, जो तलाक के बाद अपने पिता कलीम के साथ रहता है, गलत संगत में है और उसे उचित देखभाल नहीं मिल रही है।

कथित तौर पर बच्चे के धूम्रपान करने को लेकर हिरासत का विवाद

गजाला का आरोप है कि श्याम नगर निवासी कलीम अपने बच्चे से धूम्रपान करवाता है और वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड करता है। उसने अपने बेटे की सुरक्षा के लिए पुलिस हस्तक्षेप का अनुरोध किया है और हिरासत की मांग की है। जोड़े ने 2014 में शादी की थी और जनवरी 2026 में तलाक हो गया था, जिसमें उनका बेटा कलीम के साथ रहा।

गजाला का दावा है कि उसके पास बच्चे को धूम्रपान करते हुए दिखाने वाले वीडियो हैं। उसने आगे आरोप लगाया कि कलीम को पहले नशीली दवाओं से संबंधित मामले में जेल हुई थी और अब वह अपने बच्चे के भविष्य को खतरे में डाल रहा है। गजाला ने बच्चे की शिक्षा और परवरिश के बारे में भी चिंता जताई है।

शिकायतकर्ता ने 8 जून को एक मुलाकात के दौरान कलीम और उसके परिवार द्वारा दुर्व्यवहार, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की सूचना दी। सर्कल ऑफिसर अभिषेक कुमार पटेल ने बुधवार को शिकायत मिलने की पुष्टि की और कहा कि जांच जारी है।

पटेल ने कहा कि गजाला द्वारा प्रस्तुत वीडियो में बच्चे को एक कमरे में अकेले धूम्रपान करते हुए दिखाया गया है, जिसमें कलीम फुटेज में दिखाई नहीं दे रहा है। "महिला का आरोप है कि उसका पूर्व पति बच्चे को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। हम मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं, और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी," पटेल ने कहा।